

यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला कार्यक्रम अ धकारी, बाल विकास, हरिद्वार, द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गयी कसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

जिला कार्यक्रम अ धकारी, बाल विकास, हरिद्वार, के माह 06 /2016 से 08 /2017 तक के लेखा अ भलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सुधीर कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी एवं श्री जितेन्द्र सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 13.09.2017 से 23.09.2017 तक श्री दानिश इकबाल वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-प्रथम

1. परिचयात्मक:- इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री सुधीर कुमार एवं श्री देवेन्द्र कुमार दिवाकर, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी तथा श्री गौरव पंत लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 03 /06 /2016 से 15 /06 /2016 तक श्री दानिश इकबाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी /लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 05 /2014 से 05 /2016 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 06 /2016 / से 08 /2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

2. (I) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगोलिक अ धकार क्षेत्र:-

(अ) जिला कार्यक्रम अ धकारी, बाल विकास, हरिद्वार, का मुख्य कार्यकलाप जनपद में संचालित बाल परियोजनाओं के संचालन में मुख्यालय द्वारा दिये गए निर्देशों /आदेशों का प्रभावी क्रयान्वयन एवं उचित मार्गदर्शन।

(ब) जिला कार्यक्रम अ धकारी, बाल विकास, हरिद्वार, एवं इकाई द्वारा संचालित योजनाओं का भौगोलिक क्षेत्र समस्त हरिद्वार के विकास खण्ड में स्थित है।

(II) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अ धक्य (+)	बचत (-) समर्पण
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	--	--	378.50	375.48	9331.88	9096.07	--	238.83
2015-16	--	--	88.88	87.72	170.55	170.02	--	2.68
2016-17	--	--	22.20	18.96	596.34	590.22	--	9.36
2017-18 (up to Aug. 2017)	--	--	16.29	10.59	--	--	--	5.70

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत है:-

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रा. अवशेष	प्राप्त	व्यय आ धक्य (+)	बचत (-)
अप्रस्तुत					

(iii) इकाई को बजट प्राप्ति के मुख्य स्रोत निदेशक आई० सी० डी० एस० देहरादून एवं भारत सरकार से प्राप्त होते हैं। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

1. स चव 2. निदेशक 3. डी,पी,ओ, 4. सी.डी.पी.ओ 5. सुपरवाइजर 6. आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री सहायिका

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व ध: लेखापरीक्षा में जिला कार्यक्रम अ धकारी, बाल वकास, हरिद्वार, को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला कार्यक्रम अ धकारी, बाल वकास, हरिद्वार, की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03 /2017 को वस्तुत जांच हेतु चयनित कया गया। जिला कार्यक्रम अ धकारी, बाल वकास, हरिद्वार, का वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत कये गये व्यय जिला कार्यक्रम अ धकारी, बाल वकास, हरिद्वार, के आधार पर कया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग- दो (ब)

प्रस्तर 01 : वभागीय उदासीनता के कारण 6462 लाभार्थियों को रुपये 969.30 लाख का भुगतान लम्बित रहना ।

राज्य सहायतित नन्दा देवी कन्या योजना 'हमारी कन्या हमारा अभियान योजना का लाभ राज्य के उन समस्त निवासियों, जिनके परिवार में 01 जनवरी 2009 के बाद दो जी वत बालकाओं ने जन्म लिया हो तथा वे इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने की समस्त शर्तें पूरी करते हैं चाहे इसके पूर्व उनकी अन्य जी वत सन्तानें भी हों को दिया जाएगा योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता के रूप में रुपये 15000/- की धनराश तीन कशतों में प्रदान की जायेगी। प्रथम कशत बालका के अभिभावक द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के अधिकतम एक माह के अन्दर 5000/- की धनराश A/c Payee बैंक के माध्यम से कन्या के अभिभावक को प्रदान की जायेगी। शेष धनराश रुपये 10,000/- एफ. डी. के माध्यम से बैंक में कन्या तथा उसके माता-पता के नाम से संयुक्त रूप से करायी जायेगी। द्वितीय कशत के रूप में कन्या द्वारा 10 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर पुनः कन्या के माता-पता के खाते में E-transfer के माध्यम से रुपये 5000/- की धनराश हस्तांतरित की जायेगी। शेष धनराश को पुनः 8 वर्षों की अवधि के लिए एफ. डी. करा दी जायेगी जिसमें से तृतीय एवं अंतिम कशत के रूप में ब्याज सहित शेष धनराश लाभार्थी बालका को उसकी 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने, हाईस्कूल में अध्ययनरत होने तथा अववाहित होने की दशा में प्रदान की जायेगी।

योजना के तहत आर्थिक सहायता हेतु यह शर्त भी थी कि यदि बालका की अपरिहार्य कारणों से 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पूर्व मृत्यु हो जाती है तो यह धनराश राजकोष में जमा कर दी जाएगी।

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास, हरिद्वार की नन्दा देवी योजना के नमूना जांच के समय यह तथ्य प्रकाश में आया कि योजना के अन्तर्गत सम्प्रेक्षा अवधि अगस्त 2017 तक कुल प्राप्त 10295 आवेदनों के सापेक्ष मात्र 3833 लाभार्थियों को ही उक्त योजना के अन्तर्गत रुपये 15000/- की दर से भुगतान किया गया, जबकि लेखा परीक्षा (अगस्त 2017) तक 6462 लाभार्थियों को रुपये 15000/- प्रति लाभार्थी की दर से रुपये 969.30 लाख का भुगतान किया जाना लम्बित था।

उक्त के सम्बंध में इंगत किए जाने पर वभाग ने अवगत कराया कि लाभार्थियों को बजट के अभाव के कारण भुगतान नहीं किया जा सका।

वभाग द्वारा दिये गए उत्तर से स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि वभागीय उदासीनता के कारण 6462 लाभार्थियों को योजना के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ से वंचित रहना पड़ा। अतः वभागीय उदासीनता के कारण 6462 लाभार्थियों को रुपये 969.30 लाख का भुगतान लम्बित रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है

भाग- दो (ब)

प्रस्तर 02 : आगंबाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि रूपर 1606.00 लाख के अनुपयोगी रहने तथा रूपर 154.00 लाख का अनियत व्यय।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा भवन वहीन आगंबाड़ी केन्द्रों के लए पक्का भवन बनाए जाने के लए राज्य सरकारों से कार्ययोजना बनाने हेतु निर्देशित किया गया था (दिसंबर 2102), इस क्रम में उत्तराखण्ड में 1450 नए केन्द्रों का निर्माण व 113 केन्द्रों का उच्चीकरण हेतु राज्यान्श रूपर 1659.50 लाख व केंद्रान्श रूपर 4978.50 लाख कुल रूपर 6638.00 लाख की वत्तीय स्वीकृति प्रदान की थी, (उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 151 /XVII (4)/2015/2 (13) 2013 दिनांक 16.02.2015) इसी क्रम में जनपद हरिद्वार हेतु 500 नए आगंबाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु रूपर 4.50 लाख की दर से रूपर 2250.00 लाख तथा 10 केन्द्रों के उच्चीकरण हेतु रूपर एक लाख की दर से रूपर 10 लाख कुल रूपर 2260.00 लाख की वत्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया गया था। धनराशि दो कस्तों में, रूपर 158500000.00 एवं रूपर 67500000.00 कुल रूपर 226000000.00 की धनराशि आगंबाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु अवमुक्त हुई थी (फरवरी 2015)। प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी नवीन दिशा निर्देशनुसार आगंबाड़ी केन्द्रों के निर्माण की लागत संशोधित करते हुए रूपर 4.50 लाख से रूपर 7.00 लाख करते हुए निर्देश दिया गया कि एक केंद्र के निर्माण पर वभाग द्वारा मात्र रूपर 2.00 लाख की धनराशि व्यय की जायेगी और शेष राशि रूपर 5.00 लाख मनरेगा से व्यय की जायेगी, और दोनों वभागों में समन्वय स्थापित करना होगा। उत्तराखण्ड के शासन्देश संख्या 1220 /XVII (4) /2013 /2 / (4) /13 दिनांक द्वारा आगंबाड़ी केन्द्रों के निर्माण एवं पुनर्निर्माण हेतु विकास खंड को कार्यदायी संस्थाना मत किया गया था।

जिला परियोजना अधिकारी हरिद्वार के लेखा अधिकारियों की नमूना जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि जनपद हरिद्वार में कुल 3056 आगंबाड़ी केंद्र तथा 123 मनी केंद्र स्वीकृत थे जिसके सापेक्ष 2842 आगंबाड़ी केंद्र तथा 62 मनी केंद्र संचालित हो रहे थे। 2842 आगंबाड़ी केंद्र एवं 62 मनी केंद्र के सापेक्ष के सापेक्ष 1594 केंद्र करार के भवन में संचालित थे तथा 430 केन्द्रों को अन्य भवन के रूप में दर्शाया गया था शेष 880 केंद्र वभागीय अथवा शासकीय भवन में संचालित हो रहे थे। भारत सरकार के संशोधित दिशा निर्देशानुसार वभाग / जनपद में उपलब्ध राशि रूपर 2250.00 लाख से 500 के स्थान पर 1125 आगंबाड़ी केन्द्रों का निर्माण किया जा सकता था, जिसका प्रस्ताव जनपद द्वारा दिनांक 17 मई 2016 को निदेशालय को प्रेषित किया गया था परन्तु संप्रेक्ष्य तिथि तक स्वीकृति अप्राप्त थी। जांच में पाया गया कि जनपद में मात्र 654 आगंबाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु एक लाख की दर से रूपर 654.00 लाख की धनराशि, प्राप्ति तिथि के 15 से 22 माह के वलम्ब से, प्रथम कस्त के रूप में विकास खंडों को हस्तांतरित की गयी थी, ववरण निम्नवत् था -

क्रम संख्या	विकास खण्ड का नाम	बाल विकास परियोजना का नाम	केन्द्रों की संख्या	दिनांक	धनरा श
1	बहादुराबाद	बहादुराबाद प्रथम	78	13.5.2016	7800000
2	बहादुराबाद	बहादुराबाद दितीय	88	13.5.2016	8800000
3	भगवान पुर	भगवानपुर	136	13.5.2016	13600000
4	लक्सर	लक्सर	09	13.5.2016	900000
5	नरसन	नरसन	03	13.5.2016	300000
6	रुडकी	रुडकी प्रथम	20	13.5.2016	2000000
7	रुडकी	रुडकी दितीय	59	13.5.2016	5900000
8	खानपुर	खानपुर	16	13.5.2016	1600000
9	भगवानपुर	भगवानपुर	02	12.07.2016	200000
10	खानपुर	खानपुर	12	12.07.2017	1200000
11	भगवानपुर	भगवानपुर	02	20.12.2016	200000
12	लक्सर	लक्सर	52	20.12.2016	5200000
13	खानपुर	खानपुर	08	20.12.2016	800000
14	नारसन	नारसन	169	20.12.2016	16900000
			654		6,54,00,000

शेष रा श रूप 163590944.00 ब्याज सहित (मूल रा श 16,06,00,000.00 + ब्याज की रा श 29,90,944.00) जिला कार्यक्रम अधकारी के पदनाम खाते (IDBI बैंक खाता संख्या 85861355 एवं HDFC बैंक खाता संख्या 64444123 मे) मे (जून 2017) शेष / अनुपयोगी पड़ी हुई थी, जब क जनपद के 1594 केंद्र कराए के भवन मे संचालत था तथा जिन 654 केन्द्रो के निर्माण हेतु धनरा श निर्गत की गयी थी उसका निर्माण कार्य न केवल अपूर्ण था अ पतु अंतर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति अप्राप्त था।

उपरोक्त ववरण से स्पष्ट है क वभागीय उदासीनता एवं अनुश्रवन के आभाव मे 75% भारत सरकार द्वारा वत पो षत योजना आगंबाड़ी केन्द्रों का निर्माण हेतु प्राप्त धनरा श रूप 2260.00 लाख की धनरा श के उपयोग मे न केवल लापरवाही बरती गयी अ पतु रूप 163590944.00 की धनरा श (फरवरी 2015 से संप्रेक्षा ति थ सतम्बर 2017 तक) वगत 31 माह से अनुपयोगी थी जब क जनपद मे 1594 आगनबाड़ी केन्द्र कराए के भवन मे संचालत थे। आगंबाड़ी केन्द्रों के निर्माण मे हो रहे वलम्ब के कारण सरकार को अनावश्यक रूप से कराए के रूप मे अतिरिक्त व्ययभार वहन करना पड़ेगा जो क सरकार की अप्रत्यक्ष रूप से हानी थी। इसके अतिरिक्त भारत/राज्य सरकार से मात्र 500 केन्द्रो के निर्माण की अनुमति प्राप्त हुई थी, जिला कार्यक्रम अधकारी हरिद्वार द्वारा बिना शासन की अनुमति के 154 अतिरिक्त केन्द्रों के निर्माण हेतु रूप 154.00 लाख का अनिय मत व्यय कया गया जो की एक गंभीर वतीय अनिय मतता थी।

उक्त के सम्बंध में इंगत कए जाने पर वभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया। वभाग द्वारा उत्तर न दिये जाने से स्पष्ट था क भारत सरकार द्वारा वत्त पो षत योजना आगंबाड़ी केन्द्रों का निर्माण हेतु प्राप्त धनराश रूपए 1606.00 लाख की धनराश के उपयोग मे न केवल लापरवाही बरती गयी अ प्तु रूपए 163590944.00 की धनराश (फरवरी 2015 से संप्रेक्षा ति थ सतम्बर 2017 तक) वगत 31 माह से अनुपयोगी थी इसके अतिरिक्त जिला कार्यक्रम अधकारी हरिद्वार द्वारा बिना शासन की अनुमति के 154 अतिरिक्त केन्द्रों के निर्माण हेतु रूपए 154.00 लाख का अनिय मत व्यय कया गया जो की एक गंभीर वतीय अनिय मतता थी।

अतः आगंबाड़ी केन्द्रों का निर्माण हेतु प्राप्त धनराश रूपए 1606.00 लाख की धनराश वगत 31 माह से अनुपयोगी रहने तथा रूपए 154.00 लाख का अनिय मत व्यय कए जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है

भाग- दो (ब)

प्रस्तर 03 : शासनादेशों एवं वतीय नियमों व प्रावधानों के वपरीत प्राइवेट बैंक खातों में जमा धनराशि रु 22.60 करोड़ तथा चालू बैंक खाता खोले जाने से शासन को धनराशि रु 66.31 लाख की प्रत्यक्ष हानी।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 151 /XVII (4)/2015/2 (13) 2013 दिनांक 16.02.2015 द्वारा जनपद हरिद्वार हेतु 500 नए आगंबाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु रुपए 4.50 लाख की दर से रुपए 2250.00 लाख तथा 10 केन्द्रों के उच्चीकरण हेतु रुपए एक लाख की दर से रुपए 10 लाख कुल रुपए 2260.00 लाख की वतीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए दो कस्तों में, रुपए 158500000.00 एवं रुपए 67500000.00 कुल रुपए 226000000.00 की धनराशि आगंबाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु अवमुक्त किया गया था (फरवरी 2015)।

ज़िला परियोजना अधिकारी हरिद्वार के लेखा अधिकारी की नमूना जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि उक्त राशि को कोषागार से आहरित कर मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार के पी० एल० ए० खाते में रख लिया गया था, उक्त राशि को मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार के पी० एल० ए० खाते से आहरित कर दिनांक 22.03.2016 को IDBI हरिद्वार बैंक खाता संख्या 1366102000001977 में रुपए 14,09,50,000.00 की धनराशि तथा दिनांक 31.03.2016 को HDFC हरिद्वार के बैंक खाता संख्या 64444123 में रुपए 8,51,42,951.00 की धनराशि जमा किया गया दर्शाया गया था। जांच में पाया गया कि IDBI बैंक में जमा राशि रुपए 14,09,50,000.00 के सापेक्ष वगत 18 माह में कोई भी ब्याज की राशि प्राप्त नहीं हुई थी जब कि HDFC बैंक खाते में जमा राशि पर वगत 18 माह में रुपए 29,90,944.00 का ब्याज (01.04.2017 तक की स्थिति) प्राप्त हुआ था। IDBI बैंक में बचत खाता खोलने के स्थान पर चालू खाता खोलने का कोई आधार नहीं था जब कि बैंक पास बुक में स्पष्ट शब्दों में बचत बैंक पासबुक लिखा हुआ है इसके बाद भी ब्याज न मिलना यथोचित प्रतीत नहीं होता, तथा एक ही कार्य हेतु दो अलग अलग प्रकार का दो बैंकों में खाता खोलने का कोई आधार नहीं था। उक्त ववरण से परिलक्षित है कि वभाग द्वारा जानबूझ कर बैंक को लाभ पहुंचाने की मंशा से अनावश्यक रूप से IDBI बैंक में चालू खाता खोला गया और शासन को साधारण दर से न्यूनतम रुपए 66,31,216.04 की धनराशि की हानी पहुंचाई गयी। ववरण निम्नवत था-

दिनांक	जमा रा श	निकासी	अंतिम शेष	अव ध	दिनो की संख्या (X)	उक्त अव ध मे बैंक मे जमा रा श (Y)	साधारण एवं न्यूनतम दर देय ब्याज की गणना (Y*4/365*X=)
22.03.16	140950000	00	140950000	23.03.16 से 16.05.16	55	140950000	849561.64
17.05.16	00	13600000	127350000	17.05.16	01	127350000	13956.16
18.05.16	00	16600000	110750000	18.05.16 से 25.5.16	08	110750000	97095.89
26.05.16	00	900000	109850000	26.05.16 से 25.07.16	61	109850000	734339.72
26.07.16	00	200000	109650000	26.07.16 से 27.12.216	155	109650000	1862547.94
28.12.16	00	5200000	104450000	28.12.16 से 18.01.17	22	104450000	251824.65
19.01.17	00	200000	104250000	19.01.17 से 22.09.17	247	104250000	2821890.04
--	--	--	--	--	--	--	6631216.04

उपरोक्त ववरण से स्पष्ट है क वभाग द्वारा शासनादेशों एवं वतीय नियमो व प्रा वधानों के वपरीत अनावश्यक रूप से भारत सरकार द्वारा वत पो षत योजना आगंबाड़ी केन्द्रों का निर्माण हेतु प्राप्त धनरा श रुपए 2260.00 लाख की धनरा श को दो प्राइवेट बैंक खातो मे जमा कया जिसमे एक बैंक खाता चालू बैंक खाता खोला गया और शासन को जानबूझ कर संप्रेक्षा ति थ तक रुपए 66,31,216.04 (साधारण एवं न्यूनतम दर से गणना की गयी) की धनरा श की प्रत्यक्ष हानी पहुंचायी गयी थी।

उक्त के सम्बंध में इंगत कए जाने पर वभाग ने अवगत कराया क दो प्राइवेट बैंक में खाता त्रुटिवश खोला गया जिसे अ वलम्ब परिवर्तित कर दिया जायेगा भ वष्य में इस प्रकार की गलती नहीं की जायेगी।

वभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्यो क वभाग द्वारा शासनादेशों एवं वतीय नियमो व प्रा वधानों के वपरीत अनावश्यक रूप से भारत सरकार द्वारा वत पो षत योजना आगंबाड़ी केन्द्रों का निर्माण हेतु प्राप्त धनरा श रुपए 2260.00 लाख की धनरा श को दो प्राइवेट बैंक खातो मे जमा कया, जिसमे एक बैंक खाता चालू बैंक खाता खोला गया और शासन को जानबूझ कर धनरा श रुपए 66,31,216.04 (साधारण एवं न्यूनतम दर से गणना की गयी) की प्रत्यक्ष हानी पहुंचायी गयी थी।

अतः वभाग द्वारा शासनादेशों एवं वतीय नियमो व प्रा वधानों के वपरीत प्राइवेट बैंक खातो मे जमा धनरा श रुपए 2260.00 लाख तथा चालू बैंक खाता खोले जाने से शासन को धनरा श रुपए 66.31 लाख की प्रत्यक्ष हानी पहुंचाने का प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग- दो (ब)

प्रस्तर 04 : 33.30 लाख के अर्जित ब्याज एवं की धनराश को शासन को प्रेषित न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक सं. 99 / xxvii (14) 2009 दिनांक 03.12.2009 के द्वारा ब्याज की धनराश को तत्काल 0049 लेखा शीर्ष में जमा कर दिया जाना चाहिए। यदि कसी मद में ब्याज की धनराश को व्यय किया जाना हो तो वक्त वभाग से पृथक शासनादेश उपलब्ध होना चाहिए तथा उस धनराश को आगामी वर्षों में समायोजित करते हुये शेष धनराश की मांग शासन से की जाएगी।

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास हरिद्वार के योजनाओं के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि वभाग को आबंटित धनराश पर बैंक के द्वारा ब्याज दिया जाता है, वर्ष 2016-17 से 2017-18 (अगस्त 2017 तक) की अवधि में प्राप्त ब्याज की राश को 0049 में जमाने करने या धनराश को आगामी वर्षों में समायोजित करते हुये शेष धनराश की मांग शासन से नहीं किए जाने से ब्याज की धनराश रूपए 33,29,763 लम्बित हैं, जिसे तत्काल 0049 लेखा शीर्ष में जमा कर दिया जाना चाहिए, ब्याज की राश का ववरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	योजना का नाम	ब्याज की धनराश
1	जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, हरिद्वार राज्य पोषण योजनाये	4,31,770
2	जिला कार्यक्रम अधिकारी, हरिद्वार में केन्द्र पोषण योजनायें	28,97,993.00
कुल योग		33,29,763

उपरोक्त ववरण से स्पष्ट है कि बैंक में ब्याज की धनराश प्रति वर्ष बढ़ रही थी तथा वभाग द्वारा ब्याज की धनराश को शासन को वापस नहीं किया जा रहा था, जो शासनादेश के प्रति उदासीनता को प्रकट करती है।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर वभाग ने अवगत कराया कि वभाग द्वारा उक्त धनराश को अचल जमा करा दिया जायेगा।

वभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि वभाग द्वारा एक वर्ष बीत जाने के पश्चात भी वभाग द्वारा शासन को धनराश वापस नहीं की गयी। जिससे न केवल उक्त धनराश अनावश्यक रूप से अवरुद्ध है, जिसका विकास कार्यों पर उसका उपयोग सुनिश्चित नहीं किया जा सका। अतः वभाग द्वारा रू. 33.30 लाख के अर्जित ब्याज की धनराश को शासन को प्रेषित न किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग- दो (ब)

प्रस्तर 05 : धनराशि रूपए 109.50 लाख के उपयो गता प्रमाण पत्र प्राप्त कर समायोजन न कया जाना।

निदेशालय के पत्र आई. सी. डी. एस. उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या सी. - 437/बजट-4073 / 2016-17 दिनांक 20 मई 2016 एवं शासनादेश संख्या 2084/XVII (4)/2014/129/ 06 TC दिनांक 05 नवंबर 2014 के अनुसार मुख्य मंत्री वृद्ध महिला पोषण योजना के अन्तर्गत बाल विकास परियोजना अधिकारियों को मांग के अनुसार रूपए 1,00,00,000.00 धनराशि अग्रिम आहरण की स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त धनराशि की फांट करते हुये अपने अधीनस्थ संचालक सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों को उपलब्ध करायी जाएगी। आहरित धनराशि का समायोजन इसी वर्ष 2016-17 में करा लया जायेगा।

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास हरिद्वार के वर्ष 06/2016 से 08/2017 तक लेखा अभिलेखों की नमूना जांच के समय यह तथ्य प्रकाश में आया कि कार्यालय के पत्रांक C-1077/ का० क्र०-582/ 2016-17 दिनांक 02/09/2016 के द्वारा धनराशि रूपए 10000000.00 सभी बाल विकास अधिकारियों को इस निर्देश के साथ पदनाम खातों में जमा करा दिये गये, कि उक्त अग्रिम आहरण का उपभोग करने के पश्चात समायोजन बिल वाउचर इस कार्यालय को देना सुनिश्चित करें। उक्त धनराशि के सापेक्ष किसी भी बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गए। वभागीय उदासीनता के कारण इस धनराशि का समायोजन सम्प्रेक्षा तिथि तक (सितम्बर 2017) नहीं कराया गया।

इसके अतिरिक्त आई. सी. डी. एस. प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत वभाग द्वारा जून 2016 में धनराशि रूपए 5.00 लाख तथा जुलाई 2016 में 4.50 लाख कुल 9.50 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी ले कन लेखा परीक्षा तिथि (सितम्बर 2017) तक उक्त धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए गए।

उक्त ववरण से स्पष्ट है कि वभाग द्वारा उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाने में उदासीनता बरती गयी। धनराशि रूपए 109.50 लाख (10000000.00 + 950000.00 = 10950000.00) का एक वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी समायोजन नहीं कया गया जो वभाग की उदासीनता एवं लापरवाही को परिलक्षित करता है।

उक्त के सम्बंध में इंगत किए जाने पर वभाग ने अवगत कराया कि समस्त सीडीपीओ एवं प्रशिक्षण संस्थान से सूचना प्राप्त कर समायोजन कर लया जाएगा जिसे अगले संप्रेक्षण के समय प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

वभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि वभाग द्वारा एक वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी नहीं कया गया जबकि उक्त धनराशि का समायोजन वर्ष 2016-17 में करा लया लया जाना था ले कन वभाग द्वारा उसका समायोजन सम्प्रेक्षा तिथि तक नहीं कया गया।

अतः वभाग द्वारा धनराशि रूपए 109.50 लाख के उपयो गता प्रमाण पत्र प्राप्त कर समायोजन न किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो (अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो (ब) प्रस्तर संख्या	स्टेन
32/2007-08	शून्य	1,2,3	शून्य
52/2009-10	शून्य	1	शून्य
20/2010-11	1	1,2	शून्य
26/2015-16	शून्य	1,2,3,4	शून्य

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
32/2007-08	1,2,3	भाग-दो (ब)	यथावत	
52/2009-10	1	भाग-दो (ब)	यथावत	
20/2010-11	1	भाग-दो (अ)	यथावत	
	1,2	भाग-दो (ब)		
26/2015-16	1,2,3,4	भाग-दो (ब)	यथावत	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

-----शून्य-----

भाग-Vआभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु जिला कार्यक्रम अ धकारी, बाल वकास, हरिद्वार, तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गये:
 - (I) शून्य
3. सतत् अनिय मतताएं
 - (I) शून्य
4. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया:

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अव ध
1.	श्री मोहित चौधरी	जिला कार्यक्रम अ धकारी	02/08/14 से 17/11/16
2.	सुश्री शैली प्रजापति	जिला कार्यक्रम अ धकारी (प्रभारी)	23/11/16 से 06/03/17
3.	श्री अ खलेश शुक्ला	जिला कार्यक्रम अ धकारी (प्रभारी)	07/03/17 से 10/09/17
4.	सुश्री शैली प्रजापति	जिला कार्यक्रम अ धकारी (प्रभारी)	10/09/17 से वर्तमान तक

(V) लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति जिला कार्यक्रम अ धकारी, बाल वकास, हरिद्वार, को इस आशय से प्रेषित कया गया क वह लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के भीतर उसकी अनुपालन आख्या सीधे उप-महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी /सा.क्षे.